सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

प्रधान संपादकः रतन प्रकाश सिंह

www.swarajindianews.com swarajindianews swarajindianews

दैनिक सांध्यकालीन

स्वराज इंडिया

» Pg12

बंगाल में टीएमसी का जंगलराज, घुसपैठियों को बचाने की कोशिश

कानपुर, शनिवार, 20 दिसंबर, 2025
वर्षः 02, अंकः 338, पृष्ठः 8+4, मूल्यः ₹ 2/-

इनसाइड एसपी के नेतृत्व में चला 'नाइट डॉमिनेशन' अभियान.. » Pg09

जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग मामला

छत्तीस पूर्व न्यायाधीशों का विपक्ष पर जोरदार हमला!

कड़ी निंदा करते हुए प्रस्ताव को बताया न्यायपालिका पर खतरा लोकतंत्र की जड़ों पर वार और जजों को डराने की साजिश

विरोध की अपील

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

नई दिल्ली। देश के 36 पूर्व न्यायाधीशों ने विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग लाने की पहल की कड़ी निंदा की। पूर्व न्यायाधीशों ने सांसदों सहित आम लोगों से इस कदम का विरोध करने की अपील की है। साथ ही जजों ने कहा, कि यदि ऐसे प्रयासों को आगे बढ़ने दिया गया तो यह लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला होगा

शनिवार को 36 पूर्व न्यायाधीधों द्वारा लिखे गए लेटर मे कहा कि यह महाभियोग प्रस्ताव के जरिए उन जजों को डराने-धमकाने की एक खुली कोशिश है जो समाज के किसी खास वर्ग की वैचारिक और राजनीतिक उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलते। पूर्व जजों ने आगे कहा, अगर ऐसी कोशिश को आगे बढ़ने दिया गया, तो यह हमारे लोकतंत्र और

न्यायपालिका की आजादी की जड़ों को काट देगा। पूर्व जजों ने सभी से अपील की है। उन्होंने कहा, हम सभी हितधारकों - सभी पार्टियों के सांसदों, बार के सदस्यों, नागरिक समाज और आम नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वे इस कदम का पुरजोर विरोध करें और इसे शुरुआत में ही कुचल दें। लैटर में पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज कृष्ण मुरारी जे के साथ-साथ कई हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और जजों ने हस्ताक्षर किए हैं।

महाभियोग के जरिए डराने और बदनाम करने की कोशिश

जजों के संयुक्त बयान में यह भी कहा गया कि विपक्षी पार्टी का यह कदम कोई अकेला मामला नहीं है। यह भारत के हालिया संवैधानिक इतिहास के एक स्पष्ट और बहुत ही चिंताजनक पैटर्न का हिस्सा है। जजों ने कहा, राजनीतिक वर्ग के कुछ लोग जब भी फैसले उनके हितों के अनुसार नहीं होते, तो वे उच्च न्यायपालिका को बदनाम करने और डराने की कोशिश करते हैं।

पहले भी उठा था विरोध का स्वर, 56 जजों का पत्र

जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव से पहले भी न्यायपालिका के भीतर इस मुद्दे को लेकर असहमति सामने आ चुकी थी। इससे पहले 56 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और वरिष्ठ न्यायिक हस्तियों ने एक अलग पत्र लिखकर महाभियोग की पहल पर गंभीर आपत्ति जताई थी। उस पत्र में भी कहा गया था कि असहमत फैसलों के आधार पर किसी जज को निशाना बनाना न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरनाक मिसाल है। पूर्व न्यायाधीशों ने तब भी चेताया था कि यदि ऐसे राजनीतिक दबावों को सामान्य बना दिया गया तो भविष्य में कोई भी न्यायाधीश निष्पक्ष होकर फैसला देने में खुद को असुरक्षित महसूस करेगा।

आचरण पर उठाये थे सवाल

बयान में 2018 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की कोशिश का भी जिक्र किया गया। साथ ही, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, एस ए बोबडे और डी वाई चंद्रचूड के कार्यकाल के दौरान उन पर लगाए गए आरोपों का भी जिक्र किया गया। कांग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पार्टी और कई अन्य विपक्षी दलों ने 'कार्तिगई दीपम' मामले में फैसला देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के न्यायाधीश जी. आर. स्वामीनाथन को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस बीते नौ दिसंबर को लोकसभा अध्यक्ष बिरला को सौंपा था। साथ ही आरोप लगाया था कि न्यायमूर्ति स्वामीनाथन का आचरण न्यायपालिका की निष्पक्षता, पारदर्शिता और धर्मनिरपेक्ष कार्यप्रणाली के संबंध में गंभीर सवाल खड़े करता है।

अरौल में सनसनीखेज वारदात

वारदात के बाद पूरे कस्बे में दहशत और सन्नाटा

ईंट से कूचकर दो बेटों पर हमला, एक की मौत, फिर ली अपनी जान

सुसाइड नोट में पिता ने अनदेखी का लगाया आरोप

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। कानपुर कमिश्नरेट के अरौल थाना क्षेत्र में शुक्रवार को रिश्तों का खून सड़कों पर नहीं, घर के अंदर बहा। एक पिता ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपने ही दो बेटों को कमरे में बंद किया और उनके सिर ईंट से कूच डाले। चीखों से गूंजता घर कुछ ही पलों में मातम में बदल गया। एक बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा मौत से जंग लड़ रहा है। वारदात के बाद पिता ने खुदकुशी कर ली। इस खौफनाक घटना से पूरे कस्बे में सनसनी और दहशत फैल गई।

जानकारी के मुताबिक कस्बे के ओम ज्वेलर्स के मालिक 42 वर्षीय अजय कटियार ने अपनी दुकान से करीब 50 मीटर दूर स्थित मकान में अपने दोनों बेटों 7 वर्षीय शुभ और 12 वर्षीय रुद्र को एक कमरे में बंद कर ईंट से

» गंभीर रूप से घायल दूसरे बेटे का इलाज जारी।

» फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य, जांच में जुटी पुलिस

ताबड़तोड़ वार किए। इसके बाद अजय कटियार ने खुद भी आत्महत्या कर ली। देर तक दुकान न खुलने पर जब ग्राहक पहुंचे तो आसपास के लोगों को कुछ शक हुआ। स्थानीय लोग जब

अजय कटियार, हत्यारा बाप

रूद्र (12) घायल

शुभ (7) मृत

घर पहुंचे और अंदर से कोई हलचल नहीं दिखी तो परिजनों को सूचना दी गई। अनहोनी की आशंका में लोग इकट्ठा हो गए। पिता रमाशंकर कटियार भी मौके पर पहुंचे।

पुलिस को सूचना देने के बाद काफी देर तक दरवाजा खटखटाया गया। इसी दौरान गंभीर रूप से घायल बड़ा बेटा रुद्र होश में आया और किसी तरह अंदर से दरवाजा खोला। अंदर का मंजर देखकर सभी सन्न रह गए। अजय और उसके छोटे बेटे की लाश पड़ी थी। पुलिस ने बिना देर किए अजय कटियार और दोनों बेटों को बिल्हौर सीएचसी पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने अजय कटियार और छोटे बेटे शुभ को मृत घोषित कर दिया। बड़े बेटे रुद्र की हालत गंभीर होने पर उसे कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर किया गया। जहाँ उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।

विस्तृत खबर पृष्ठ 04 पर...

10 किमी एलीवेटेड रोड को मिली मंजूरी, कानपुर होगा जाम मुक्त

सड़क परिवहन मंत्रालय से सैद्धांतिक सहमति, वन व रेल मंत्रालय से एनओसी प्रक्रिया शुरू

» प्रमुख संवाददाता/स्वराज इंडिया

कानपुर। शहर की यातायात व्यवस्था को बड़ी राहत देने वाली गोल चौराहे से रामादेवी तक प्रस्तावित एलीवेटेड रोड परियोजना को आखिरकार केंद्र से हरी झंडी मिल गई है। सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने परियोजना को सैद्धांतिक सहमति देते हुए आगे की कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद पीडब्ल्यूडी एनएच ने निर्माण शुरू होने से पहले की औपचारिकताएँ तेज कर दी हैं।

पीडब्ल्यूडी एनएच ने एलीवेटेड रोड निर्माण के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग के साथ ही रेल मंत्रालय से एनओसी के लिए आवेदन कर दिया है। रेल मंत्रालय की अनुमति के लिए पाँच लाख रुपये की फीस भी जमा कर दी गई है, जबकि वन विभाग के एस्टीमेट मिलने के बाद आगे का कदम उठाया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, डीपीआर और डिजाइन को मंत्रालय के मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है और नए वर्ष की शुरुआत में परियोजना को अंतिम स्वीकृति और लगभग 1500 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी मिलने की संभावना है।करीब 10.2 किलोमीटर लंबी यह एलीवेटेड रोड गोल चौराहा, झकरकटी बस अड्डा, जरीब चौकी और सीओडी क्रॉसिंग जैसे प्रमुख इलाकों में यातायात का दबाव काफी हद तक कम करेगी। इन स्थानों पर एलीवेटेड रोड से चढऩे-उतरने के लिए रैंप भी बनाए जाएंगे। मंत्रालय की टीम ने पहले निरीक्षण के दौरान जमीन अधिग्रहण से बचते हुए डिजाइन में सुधार के निर्देश दिए थे, जिनके अनुसार डीपीआर में करीब 20 संशोधन किए गए।विभागीय इंजीनियरों का कहना है कि अंतिम स्वीकृति मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और निर्माण कार्य में लगभग तीन वर्ष का समय लगेगा।

> एलीवेटेड रोड की डीपीआर मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार भेजी गई है। निर्माण से पूर्व वन एवं रेल मंत्रालय की एनओसी प्रक्रिया चल रही है। नए वर्ष में स्वीकृति मिलने की पूरी उम्मीद है।
>
> रवीन्द्र जायसवाल, प्रभारी अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी एनएच

प्रेमिका ने कराई प्रेमी की हत्या, 49 दिन बाद जंगल से मिला कंकाल

» 13 साल की बेटी पर बुरी नजर डालने से नाराज महिला ने रची साजिश

» भतीजे संग मिल गला दबाया, शव जंगल में फेंका, पुलिस ने किया खुलासा

» प्रमुख संवाददाता/स्वराज इंडिया

कानपुर। चौबेपुर के रौतापुर गांव से 49 दिन से लापता युवक की हत्या उसी की प्रेमिका ने अपने भतीजे के साथ मिलकर कराई थी। पुलिस ने महिला और उसके भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने पूछताछ में अपराध स्वीकारते हुए बताया कि मृतक उसकी 13 वर्षीय बेटी पर बुरी नजर डालता था और गलत संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था। यही कारण उसकी हत्या की वजह बना।

महिला की निशानदेही पर पुलिस ने शिवराजपुर क्षेत्र के शाह निवादा गांव के जंगल से युवक का कंकाल बरामद कर लिया है।अविवाहित 35 वर्षीय गोरेलाल का गांव की ही एक महिला से लंबे समय से प्रेम संबंध था। 31 अक्टूबर की रात से अचानक लापता होने के बाद परिजनों ने 2 नवंबर को उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस लगातार मोबाइल लोकेशन व सर्विलांस के आधार पर तलाश कर रही थी। शुक्रवार को हिरासत में लिए जाने के बाद महिला ने पूरे घटनाक्रम का सच सामने रख दिया।महिला ने बताया कि चार साल से चल रहे संबंधों के दौरान गोरेलाल ने उसकी बड़ी बेटी को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया था। विरोध करने पर युवक इकलौते बेटे को जान से मारने की धमकी देता था। इसी दबाव और भय के चलते महिला ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। 31 अक्टूबर की रात वह उसे शादी कराने के बहाने मायके ले गई। वहां पहले शराब पिलाई और फिर भतीजे के साथ मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को घसीटकर जंगल में फेंक दिया गया।

डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस ने पूरे मामले का राजफाश कर मृतक का कंकाल बरामद कर लिया है। फोरेंसिक जांच शुरू कर दी गई है। सर्विलांस के जरिए मोबाइल की गतिविधियां पकड़ में आने के बाद पुलिस सुराग तक पहुंची। महिला के साथ शामिल गांव का एक युवक अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।

न कोई दुकान, न गोदाम फिर भी किया करोड़ों का टर्नओवर!

कानपुर में टैक्स चोरी करने वाली पकड़ी गई दो फर्जी फर्म

» प्रमुख संवाददाता/स्वराज इंडिया

कानपुर। यूपी के कानपुर में सालों से कागजों पर कारोबार कर रही दो फर्मों का खुलासा हुआ है। फर्जी कागजातों पर आईटीसी का लाभ लेकर 6.46 करोड़ टैक्स चोरी को भी अंजाम दिया। विभाग के उपायुक्त ने तीन महिलाओं समेत पांच के खिलाफ बेकनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। फर्जीवाड़ा के पीछे संगठित गैंग की आशंका जताई जा रही है। एसजीएसटी के उपायुक्त धीरेंद्र कुमार की ओर से दर्ज एफआईआर के अनुसार, हीरामनपुरवा में आवासीय पते पर 2018 से संचालित कारोबारी फर्मों के फर्जी होने का खुलासा हुआ है। फुटवियर, प्लास्टिक आइटम का कारोबार करने वाली कोमल ट्रेडर्स का जीएसटी नंबर शबाना नाम की महिला के नाम से है। 2018-19 में नौ करोड़ 71 लाख कारोबार दिखाया गया। वहीं 2019-20 में फर्म ने 19 करोड़ नौ लाख रुपये का व्यापार दिखा गया है।

इस हिसाब से फर्म पर दो साल का पांच करोड़ 14 लाख रुपये टैक्स हुआ। फर्म ने बोगस कागजात के आधार पर आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ भी उठा लिया। फर्म ने पांच करोड़ 14 लाख का गलत तरीके से फर्जी आईटीसी का लाभ लेते हुए टैक्स में समायोजित कर लिया। इसी तरह हीरामन पुरवा में ही स्टार इंटरप्राइजेज ने भी विभाग को धोखे में रखा। आवासीय पते पर तब्बुसम फातिमा नाम की महिला के नाम से संचालित इस फर्म ने 2019-2020 में सात करोड़ 35 लाख का कारोबार दिखाया। फर्म ने भी बोगस दस्तावेजों के आधार पर एक करोड़ 32 लाख रुपये का आईटीसी का लाभ हासिल कर लिया था।

एसआईबी के छापे में नहीं मिले थे संचालन के साक्ष्य

उपायुक्त ने बताया कि एसआईबी ने कई साल पहले दोनों फर्मों के दिए पते पर छापा मारा था। उस दौरान दोनों फर्मों का पता आवासीय निकला था, जबकि यहां किसी भी प्रकार की कोई व्यापारिक गतिविधियां नहीं मिली थीं। जांच में आसपास के लोगों ने फर्म के संचालन से अनभिज्ञता जताई थी।

पति-पत्नी गैंग बनाकर कर रहे फर्जीवाड़ा

उपायुक्त धीरेंद्र कुमार ने बताया कि जांच के दौरान इस आशंका के प्रबल साक्ष्य मिले हैं कि गैंग बनाकर फर्जीवाड़ा का धंधा किया जा रहा है। कोमल ट्रेडर्स की गडरिया मोहाल निवासी शबाना व स्टार इंटरप्राइजेज की काकादेव निवासी तब्बुसम, फातिमा के अलावा दिलशाद आलम, नौशाद, अनवरगंज के महफूज के अलावा मर्सरत को नामजद किया गया है। दिलशाद और मर्सरत दोनों पति-पत्नी हैं। आगे यह देखा जाएगा कि फर्म संचालन करने वाली महिलाओं के कहीं कागजात धोखे से तो इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं।

नगर निगम में जन्म-मृत्यु के अभिलेख हुए डिजिटल

नगर आयुक्त उपाध्याय ने पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। नगर निगम में पारदर्शिता बढ़ाने और कार्यप्रणाली को अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से तकनीक के प्रभावी उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। नगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम द्वारा वर्ष दो हजार आठ से पूर्व के जन्म और मृत्यु से संबंधित हस्तलिखित अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है।इसके साथ ही वर्ष दो हजार आठ से दो हजार अठारह तक नगर निगम की वेबसाइट के माध्यम से निर्गत जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्रों के अभिलेख भी डिजिटल रूप में ऑनलाइन कर दिए गए हैं। वहीं वर्ष दो हजार उन्नीस से वर्तमान तक के सभी जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र पहले से ही ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

इस नई व्यवस्था के लागू होने से अब आम नागरिकों को पुराने अभिलेखों की प्रमाणिकता जांचने के लिए नगर निगम मुख्यालय के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्रों से जुड़े सभी अभिलेखों का सत्यापन अब संबंधित जोनल कार्यालयों में जोनल अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिससे प्रमाण-पत्र निर्गमन में होने वाले अनावश्यक विलंब पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार यह व्यवस्था दिनांक बीस दिसंबर दो हजार पच्चीस से प्रभावी कर दी गई है।

साथ ही जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए नागरिक सुविधा केंद्र ऐप की शुरुआत भी की गई है।

नागरिक सुविधा केंद्र ऐप के माध्यम से आवेदक जन्म या मृत्यु से संबंधित आवेदन ऑनलाइन कर सकेंगे। आवेदन करते समय मूल दस्तावेजों के अनुसार सही और पूर्ण विवरण, जैसे आवेदक का नाम,

सूचनादाता का नाम, आवेदक से सूचनादाता का संबंध, जन्म तिथि या मृत्यु तिथि आदि अंकित करना अनिवार्य होगा।

ऑनलाइन पंजीकरण के बाद आवेदक ऐप से प्राप्त पंजीकरण संख्या के साथ संबंधित जोनल कार्यालय स्थित नागरिक सुविधा केंद्र के पटल पर आवेदन जमा कर सकेंगे। नगर निगम का कहना है कि इस पहल से नागरिकों को समय की बचत होगी और जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ-साथ सुविधा भी बढ़ेगी।

नागरिक सुविधा केंद्र ऐप को नीचे दिए गए लिंक, क्यूआर कोड को स्कैन करके अथवा गूगल प्ले स्टोर पर नागरिक सुविधा केंद्र ऐप खोज कर डाउनलोड किया जा सकता है।

केडीए कर्मचारी नेता की लगाई होर्डिंग बनीं चर्चा का विषय

कानपुर विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर हैं भ्रष्टाचार के आरोप

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में आ गया है। प्राधिकरण में कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले अनुसूचित जाति के कर्मचारी राकेश रावत को ही निशाना बनाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय राकेश रावत पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाकर जबरन विभागीय कार्रवाई की गई।

पीड़ित कर्मचारी नेता राकेश रावत का कहना है कि उन्होंने केडीए में लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार की परतें खोलते हुए उच्च अधिकारियों और प्रदेश सरकार तक शिकायत भेजी, लेकिन जांच के नाम पर उलटा शिकंजा उन पर ही कस दिया गया। उनका आरोप है कि यह कार्रवाई उन्हें डराने और चुप कराने की मंशा से की गई, ताकि भ्रष्टाचार का खेल निर्बाध चलता रहे।

मामले ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब केडीए कार्यालय के बाहर बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए गए। इन होर्डिंग्स में तत्कालीन अधिकारियों अरविंद सिंह, शत्रोहन वैश्य, गुणा केश शर्मा, अवनीश सिंह, और शशिभूषण राय सहित कई अन्य अधिकारियों पर पद के दुरुपयोग, तानाशाही रवैये और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। होर्डिंग्स में यह भी दावा किया गया है कि केडीए के भीतर आज भी एक संगठित भ्रष्टाचार सिंडीकेट सक्रिय है, जिस पर शासन की निगाहें पड़ने से पहले ही नजरें फेर ली जाती हैं।

कर्मचारी नेता द्वारा लगाए गए इन होर्डिंग्स ने प्राधिकरण के गलियारों में खलबली मचा दी है। कर्मचारी संगठनों और सामाजिक संगठनों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि यदि शिकायतकर्ता ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक और ईमानदार कर्मचारी कैसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं।सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश में सख्त प्रशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार तक शिकायत पहुंचने के बावजूद अब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उलटे, शिकायत करने वाले दलित कर्मचारी को मानसिक और प्रशासनिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।

अब यह मामला सिर्फ एक कर्मचारी का नहीं, बल्कि शासन-प्रशासन की साख से जुड़ गया है। यदि समय रहते निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो यह संदेश जाएगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत सच्चाई बोलने वालों को ही चुकानी पड़ती है।

अपनों के दूरी बनाने से मानसिक अवसाद में जकड़ गया था अजय!

सुसाइड नोट में लिखा पूज्य पिता जी उतने ही बेटों को जन्म देना चाहिए जितने को संभाल सको

» अकेलेपन में वर्षों से जल रहे अजय ने उठाया आत्मघाती कदम।

» प्रेमिका बनी पत्नी की मौत से टूट गया था।

» रिज़वान कुरैशी, स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। वह दुकानदार था... एक अच्छा ज्वैलर्स था... सबको अपनापन बांटता था... और अपने पेशे से न्याय करता था...लेकिन यही व्यक्ति निजी जीवन में बेहद अकेला, खामोश,अवसादग्रस्त तनाव से भरा हुआ था और यह कहानी उसका सुसाइड नोट चीख- चीख कर कह रहा है। अगर इस सुसाइड नोट की माने तो वह अपने बच्चों के लिए चिंतित था.... शायद बेइंतहा प्यार करता था उन्हें और अंततः यह भरपूर प्रेम क्रूरता की सारी हदें पार कर गया। वह हत्या करके ही सही बच्चों को साथ ले जाना चाहता था। यह कहानी ज्वैलर्स अजय कटियार की है जिसने अपने बच्चों को मारकर खुद सुसाइड कर लिया।

अजय कटियार, हत्यारा बाप

रूद्र (12) घायल

शुभ (7) मृत

इसे भाग्य ही कहा जाएगा कि एक बच्चा अस्पताल में जिन्दिगी की लड़ाई लड़ रहा है। अजय के जीवन की जंग उसके प्रेम विवाह से शुरू होती है जहां उसका विवाह तो हो गया लेकिन घर वालों ने उसे ठुकरा दिया। ऐसा लोगों का कहना है। यहीं से अजय अकेला पड़ गया। हालात नहीं सुधरे और 19 दिसंबर 2022 को अजय का पत्नी के साथ

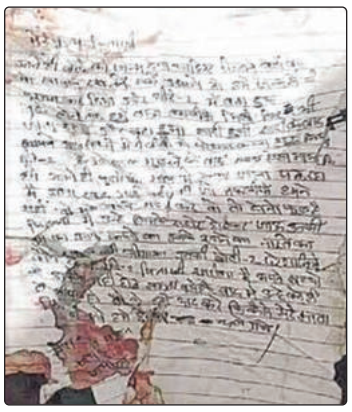

झगड़ा हुआ और उसकी मौत हो गई। जिसका हत्या का आरोप अजय के माथे पर लगा। लेकिन बच्चों की खातिर मामले को शांत कर समझौता कर लिया गया। लेकिन रिश्तों में खून अभी और बहना था..... समय गुजरा घटना कमजोर पड़ती गई। लेकिन अजय के अंदर अपनों द्वारा छोड़ दिए जाने का दर्द इतना बढ़ा कि 19 दिसंबर 2025 को तीन साल

फॉरेंसिक जांच के बाद घटनास्थल से अहम सबूत झोले में भरकर ले जाता पुलिस कर्मी

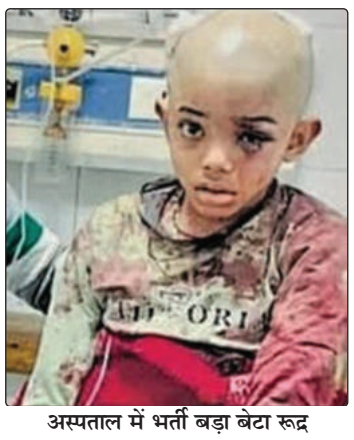

अस्पताल में भर्ती बड़ा बेटा रूद्र

बाद उसी तारीख को अजय का अवसाद क्रूरता की कहानी बन गया। जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है। ओम ज्वेलर्स के मालिक अजय कटियार उर्फ लालू ने घटना को अंजाम देने से पहले अपने पिता के नाम एक सुसाइड नोट भी लिखा। अजय ने उसमे लिखा।....मेरे पूज्य पिताजी उतने ही बेटों को जन्म देना चाहिए जो संभाल कर रख सकें... आपने तो जन्म से ही पराया कर दिया... धीरे-धीरे बड़ा हुआ। बड़े होने तक बहुत तकलीफें मिली... फिर भी जीता रहा और शादी भी हुई... आप सबने मेरी बीवी को भी परेशान करना शुरू किया...धीरे-धीरे 8-10 साल गुजारने के बाद ऐसा समय आया कि हमें अपने पुत्रों को साथ लेकर जाना पड़ रहा है.... मैं इतना खुदगर्ज नहीं जो तकलीफें हमने सहीं वह मेरे बच्चे भी सहन करें। वह तो दोनों फूल हैं..... पिताजी मैं उनको किसके सहारे छोड़ कर जाऊं। उनके कपड़े और खाने-नाश्ते का इंतजाम कौन करेगा। उनकी छोटी-छोटी परेशानी कौन देखेगा। पिताजी इसलिए मैं अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता। ताकि बाद में उन्हें कोई तकलीफ हो और वह कहें कि कैसे मेरे मा- पिता थे। हमें छोड़कर चले गए। अजय के सुसाइड नोट ने यह साफ कर दिया वह साइको ही था। उसके इस सुसाइड नोट से लग रहा है वह अपने पिता की परवरिश से खुश नहीं था। अरौल इंस्पेक्टर जनार्दन यादव ने बताया कि सुसाइड नोट की भी जाँच की जा रही है।

पत्नी की हत्या का आरोप भी लगा था अजय पर!

बच्चों की मौसी अर्चना ने बताया कि तीन साल पहले इसी तारीख को उसकी बहन यानी अजय की पत्नी की भी हत्या हो गई थी। आरोप है कि अजय ने पहले बेरहमी से मारपीट की और फिर ईंट से कूंचकर उसकी जान ले ली। इस घटना को लेकर अर्चना ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन स्थानीय दबाव और नाते रिश्तेदारों के चलते मामला सुलह-समझौते में तब्दील हो गया। अर्चना के मुताबिक, समझौते की शर्त यह रखी गई थी कि अजय द्वारा अर्जित सारी संपत्ति उसके बच्चों के नाम की जाएगी। इसके बाद मकान और खेत बच्चों के नाम कर दिए गए। लेकिन हिंसा और पारिवारिक तनाव की जड़ यहीं पर खत्म नहीं हुई। जिसका परिणाम आज सबके सामने है।

करीब आधा घंटे बंद रहा सीसीटीवी कैमरा

घटना की जानकारी मिलते ही जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुँचे। एसीपी मंजय सिंह ने इंस्पेक्टर जनार्दन यादव के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस की सूचना पर फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुँची और साक्ष्य एकत्र किए।

फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल से खून से सनी दो ईंटें, जहरीले पदार्थ का एक डिब्बा, दो गिलास और एक फंदा बरामद हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो उसमे सुबह करीब साढ़े छह बजे अजय झाड़ू लगाता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद सुबह 8:30 बजे दोनों बच्चे घर के अंदर बरामदे में नजर आए। इसके बाद अजय ने करीब आधे घंटे के लिए सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया, फिर उसे दोबारा चालू किया। पुलिस के अनुसार अजय ने पहले जाल के सहारे फंदा लगाने का प्रयास किया, लेकिन सफल न होने पर उसने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पूरा घर सीसीटीवी से लैस होने के बावजूद घटना को अंजाम देने का कोई भी तरीका पुलिस के हाथ नहीं लगा।

अजय ने किया था प्रेम विवाह, घर वाले थे नाखुश

सर्राफा कारोबारी अजय ने करीब 15 वर्ष पहले अपने पैतृक गांव हासिमपुर से लगभग पांच किलोमीटर दूर स्थित केशवपुर गांव की अलका से प्रेम विवाह किया था। यह रिश्ता अजय की मर्जी से तय हुआ था, लेकिन घरवालों को यह विवाह स्वीकार नहीं था। इसी बात को लेकर परिवार में आए दिन विवाद होते रहते थे। पारिवारिक तनाव से दूरी बनाने के लिए अजय ने बाद में अरौल कस्बे के आचार्य नगर में प्लॉट खरीदा और वहां मकान बनवाकर अलग रहने लगा।

मानसिक अवसाद के चलते ही होती हैं ऐसी घटनाएं...!

जो माता-पिता अपने बच्चों से जान से ज्यादा प्यार करते हैं, वे ही उनकी जान कैसे ले सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है,भले ही यह कितना ही अप्रत्याशित क्यों न हो। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे Filicide-Suicide (संतान हत्या के बाद आत्महत्या) कहा जाता है। इसके पीछे मुख्य रूप से परोपकारी मोह (Altruistic Filicide) सबसे आम और हृदय विदारक कारण है। इसमें माता-पिता को लगता है कि वे बच्चों को बचा रहे हैं। लेकिन दुनियां को क्रूर समझने वाले माता-पिता गंभीर अवसाद में होते हैं और उन्हें लगता है कि उनके जाने के बाद बच्चे इस क्रूर दुनिया में अकेले और दुखी रहेंगे। इसलिए वे ऐसा कदम उठाते हैं।

आरती यादव,
प्रवक्ता, मनोविज्ञान
राम सहाय इंटर कॉलेज बैरी,
शिवराजपुर, कानपुर

साइको किलर बनने की राह पर चल पड़ा था अजय

पत्नी की ईंट से कूंचकर हत्या के आरोपों से घिरा अजय मानो धीरे-धीरे एक साइको किलर की मानसिकता की ओर बढ़ता चला गया। तीन साल पहले जिस दिन, जिस महीने उस पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगा था। ठीक उसी तारीख़ और उसी महीने उसने अपने ही घर में दो मासूम बच्चों पर ईंट से जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद खुद भी मौत को गले लगा लिया।जिसमे उसका बड़ा बेटा बच गया। इस घटना से ऐसा प्रतीत होता है मानो कि वह तीन साल पहले हुई पत्नी की मौत को एक पल के लिए भी नहीं भूल पाया था... और वह जिंदा तो था लेकिन अंदर से पूरी तरह मर चुका था.. इसलिए उसने इस घटना को अंजाम देने के लिए वही तारीख चुनी।

स्वराज इंडिया

www.www.swarajindianews.com.com

वैचारिक मंच

सम्पादकीय

जिम्मेदार व्यवहार रोकेगा रोड एक्सीडेंट

लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का वह बयान तार्किक ही है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं मानवीय व्यवहार से जुड़ी हैं। निश्चय ही यदि वाहन चालकों को सड़क व्यवहार के प्रति जागरूक किया जाए और हम जिम्मेदारी-सावधानी से वाहन चलाएं तो हर साल हजारों जिंदगियां बचायी जा सकती हैं। भारत में दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले कम वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं, लेकिन सड़क हादसों के मामले में हम अव्वल हैं। विडंबना देखिए कि एक साल में देश के भीतर करीब पांच लाख सड़क हादसे दर्ज किए जाते हैं। बड़ी संख्या उन हादसों की भी है जो छोटे शहरों व भीतरी इलाकों में होते तो हैं, लेकिन दर्ज नहीं होते। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश में हर साल करीब 1.8 लाख लोग इन हादसों में मारे जाते हैं। लाखों लोग इन हादसों में घायल होते हैं। हजारों लोग ऐसे भी होते हैं जो हादसों के बाद जीवनपर्यंत सामान्य जीवन नहीं जी पाते हैं। दुखद स्थिति यह भी है कि मरने वालों में सर्वाधिक संख्या युवाओं की होती है। एक आंकड़े के अनुसार मरने वालों में 66 फीसदी लोग 18 से 34 साल के बीच होते हैं। जो अपने परिवार के कमाने वाले व्यक्ति होते हैं। फलत- हादसे के बाद कई परिवार गरीबी के दलदल में धंस जाते हैं। दरअसल, सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण तेज गति से वाहन चलाना भी है। सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि ओवर स्पीडिंग से 68 फीसदी से अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। वहीं निर्धारित स्पीड से अधिक तेजी से वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं के चलते ही 68 फीसदी मौतें भी होती हैं। निश्चित रूप से ये हादसे व मौतें मानवीय व्यवहार की कमजोरी से जुड़े हैं। जहां देश में राष्ट्रीय राजमार्गों व एक्सप्रेस-वे का तेजी से विस्तार हुआ है तो बेहतर सड़कों में वाहन चालकों की गति अनियंत्रित हो चली है। जो कालांतर सड़क हादसों की वजह बनती है।

यह विडंबना है कि हम अकसर सुरक्षा नियमों की अनदेखी करते हैं। आज की युवा पीढ़ी हेलमेट पहनने से परहेज करती है। यह जानते हुए कि हादसों में सिर की चोट जानलेवा बन जाती है। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में हेलमेट न लगाने के कारण 54,568 लोगों की मौत हुई। वहीं सीट बेल्ट न लगाने से 16 हजार से अधिक यात्रियों की जान गई।

इन हादसों की एक बड़ी वजह ऐसे अकुशल चालकों का होना भी था, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था। आंकड़ों के अनुसार दुर्घटनाओं के लिये जिम्मेदार चालकों में 33,827 ऐसे थे जिनके पास लाइसेंस नहीं थे। देश में बड़ी संख्या ऐसे चालकों की होती है, जो मेडिकली फिट नहीं होते। इसके अलावा जुगाड़ से ले-देकर लाइसेंस बनाने वालों की भी कमी नहीं है। वे वाहन चलाने की पर्याप्त योग्यता व अनुभव के बिना ही चालक बन बैठते हैं। हाल के वर्षों में नशे की हालात में वाहन चलाने का फैशन भी बना है। कई हादसों के बाद खुलासा हुआ कि फलां चालक नशे में धुत था। हालांकि, महानगरों व शहरों में नाका लगाकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों की पकड़-धकड़ की जाती है।

नाम बदलने की नीति व नीयत के सवाल

यशवंत सचदेव

किसी योजना में बदलाव का मतलब यही नहीं होना चाहिए कि उससे राजनीतिक स्वार्थ की गंध आये। देश-विदेश में गांधी की मूर्तियों के सम्मुख सर झुकाने से नहीं, गांधी के दिखाये मार्ग पर चलने से बदलाव आयेगा। गांधी का नाम...किसी योजना में बदलाव का मतलब यही नहीं होना चाहिए कि उससे राजनीतिक स्वार्थ की गंध आये। देश-विदेश में गांधी की मूर्तियों के सम्मुख सर झुकाने से नहीं, गांधी के दिखाये मार्ग पर चलने से बदलाव आयेगा। गांधी का नाम हटाने की मानसिकता गांधी को नकारने का ही संकेत देती है।बचपन में दोस्तों के बीच बहस के दौरान हम अक्सर एक वाक्य बोला करते थे-'अगर मेरी बात ग़लत सिद्ध हो तो मेरा नाम बदल देना'। हम नाम की दुहाई क्यों देते थे, पता नहीं, पर इतना अवश्य पता है कि हमारी मित्र-मंडली में नाम बदलने वाली इस बात का महत्व बहुत माना जाता था। नाम बदलने वाली यह बात आज अचानक 'मनरेगा' के नाम बदलने की सरकार की घोषणा के संदर्भ में याद आ रही है।

वर्ष 2005 में केन्द्र में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने 'मनरेगा' नाम से एक योजना प्रारंभ की थी। 'मनरेगा' का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह योजना नागरिकों को काम के अधिकार को दृष्टि में रख कर लागू की गयी थी, जिसमें किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को साल में कम से कम सौ दिन का रोज़गार उपलब्ध कराने की सरकार की गारंटी थी। जब यह योजना लागू हुई तो इस पर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे थे। फिर जब केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनी तो प्रधानमंत्री ने इसे 'कांग्रेस की विफलताओं का जीता-जागता स्मारक' कहा था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि 'मैं इसे बंद नहीं करूंगा। मेरी राजनीतिक सोच यह बताती है कि इसे कांग्रेस की विफलता के स्मारक के रूप में गाजे-बाजे के साथ बनाये रखना चाहिए'। सो, अपने ग्यारह साल के शासन में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे बनाये रखा। वस्तुत- यह एक ज़रूरत थी, और किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य में ऐसी ज़रूरत को दरकिनार नहीं किया जा सकता। मनरेगा की यह योजना कितनी उपयोगी सिद्ध हो रही है अथवा इसमें पहले कितना भ्रष्टाचार था और अब कितना भ्रष्टाचार है, यह मुद्दा अलग चर्चा का विषय हो सकता है। आज इस बारे में चर्चा करने की आवश्यकता सरकार की इस घोषणा से उत्पन्न हो गयी है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस योजना का नाम बदलना ज़रूरी हो गया है। सरकार ने निर्णय किया है कि अब इसे 'पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार' योजना कहा जायेगाङ्क संक्षेप में 'जी रामजी विधेयक'। नाम बदलने के अलावा और भी कुछ बदलाव इस योजना में किए जा रहे हैं।बदलाव पृथक बहस का विषय है, आज जो विवाद चल रहा है, वह यह है कि इस जन-उपयोगी योजना के नाम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम सरकार क्यों हटा रही है? इस संदर्भ में अब तक जो जवाब दिये जा रहे हैं, वे इस बात तक सीमित हैं कि आज़ादी के सौवें साल तक उन्नत भारत का सपना साकार करने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। कहा यह भी जा रहा है कि नाम से क्या फर्क पड़ता है, महात्मा गांधी की जगह 'पूज्य बापू' का ही तो नाम दिया जा रहा है, फिर इसमें तो गांधी जी के आराध्य राम का नाम भी है। ऐसे में नाम बदलने से किसी को शिकायत क्यों होनी चाहिए?शिकायत इसलिए है कि बात सिर्फ महात्मा गांधी की जगह बापू नाम करने तक ही सीमित नहीं हैङ्कबात सरकार की नीयत की है। संसद में 'मनरेगा' की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी 'राजनीतिक सूझ-बूझ' का भी हवाला दिया था। आज योजना का नाम बदलने के पीछे इस राजनीतिक सूझ-बूझ की बात नहीं कही जा रही है, पर आरोप भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर नाम बदलने वाली राजनीति का ही लग रहा है।पिछले दस-बारह साल में नाम बदलने वाली इस राजनीति की अक्सर चर्चा होती रही है। कांग्रेस लगातार यह आरोप लगाती रही है कि उसकी योजनाओं के नाम बदलकर वर्तमान सरकार यश लूटना चाहती है। इस नीति पर भी चर्चा हो सकती है, पर आज आवश्यकता इस बात की है कि योजनाओं, जगहों, नगरों आदि के नाम बदलकर की जाने वाली राजनीति का औचित्य क्या है? पिछले दस-बारह साल की ही बात करें तो पता चलता है कि न जाने कितनी जगहों, सड़कों आदि के नाम बदलकर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश होती रही है। और यह लाभ उठाने का काम सिर्फ भाजपा ही नहीं कर रही। अलग-अलग समय पर अलग-अलग सरकारें ऐसा करती रही हैं और अब तो जैसे यह परंपरा बन गयी है। राजधानी दिल्ली में न जाने कितनी सड़कों के नाम बदल दिये गये हैं। पर समझने की बात यह है कि हर बदलाव प्रगति नहीं होता। अतार्किक परिवर्तनों से बात नहीं बनती। ठोस परिवर्तनों की आवश्यकता है। सांस्कृतिक नवीनीकरण का तर्क अथवा इतिहास की कथित भूलों की दुहाई देकर बदले जाने वाले नाम भी कुल मिलाकर संकुचित सोच को ही दर्शाते हैं। आवश्यकता इस सोच से उबरने की है। यह भी समझना ज़रूरी है कि सिर्फ नाम बदलने से स्थितियां नहीं बदल जातीं।'मनरेगा' योजना में यदि कोई बुराई थी तो इसलिए नहीं थी कि उसके साथ गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ था और सिर्फ इसलिए नये नाम वाली 'मनरेगा' अच्छी नहीं हो जायेगी कि उसके साथ अब भगवान राम का नाम जुड़ेगा। जिस रामराज्य की दुहाई बापू दिया करते थे, वह तुलसी का वह शासन था जिसमें 'नाही दरिद्र कोई दुखी न दीना' की स्थिति थी जहां जनता को 'दैहिक, दैविक भौतिक तापों' से मुक्ति मिली हुई थी। राम-राज्य में राजा राम जनता से कहते हैं कि यदि उनसे कोई चूक होती है तो वह अपने राजा को दंड दे सकती है।इस राम-राज्य को 'राजनीतिक सूझ-बूझ' से लिए गए निर्णयों से जोड़ना राम-राज्य की परिकल्पना से ही खिलवाड़ है।'

मनरेगा' का नाम-परिवर्तन शासन की राजनीतिक सूझ-बूझ पर आधारित होने का मतलब यही हो सकता है कि निर्णय के पीछे कहीं कोई राजनीतिक उद्देश्य है।

भारत के लिए चिंता की बात है अराजकता

बांग्लादेश में अस्थिरता

डा. कृष्ण कुमार

हसीना सरकार के जाने के बाद जमात-ए-इस्लामी जैसे समूह सक्रिय हो गए हैं और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। भारत ने बार-बार इस पर विरोध जताया है। हादी जैसे भारत-विरोधी नेता, जो कभी 'ग्रेटर बांग्लादेश' जैसे विचारों से जुड़े थे, प्रदर्शनों में भारत को निशाना बनाकर इस भावना को प्रदर्शित करते रहे हैं।बांग्लादेश में 'कट्टरपंथ' की विभीषिका चरम पर है। हिंसा के इस दौर में भारत विरोध और मीडिया हाउस निशाने पर हैं। निष्पक्ष लिखने वाले पत्रकारों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। वहां का हिंदू समुदाय, पत्रकार और मीडिया हाउस भय की स्थिति में हैं।

वर्तमान में, बांग्लादेश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति संवेदनशील हो चुकी है। दिसंबर के मध्य में घटित घटनाओं ने इस देश को नए उथल-पुथल की ओर धकेल दिया है। शरीफ उस्मान हादी, जो इंक़लाब मंच के प्रवक्ता और 2024 के छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे, की मौत ने व्यापक विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है। हादी, जो भारत-विरोधी बयानबाजी और शेख हसीना के कट्टर आलोचक के रूप में जाने जाते थे, की हत्या ने न केवल आंतरिक अस्थिरता को बढ़ावा दिया, बल्कि भारत के साथ संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया है।पिछले दिनों ढाका और अन्य शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें प्रमुख मीडिया हाउस जैसे 'द डेली स्टार' और 'प्रथम आलो बांग्ला' समाचार पत्र के कार्यालयों पर हमले और आगजनी की घटनाएं घटीं। वहीं, भारत ने सुरक्षा चिंताओं के चलते अपने वीजा केंद्र बंद कर दिए, जो द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट का स्पष्ट संकेत है। इन घटनाओं से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जो नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में है, के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। कट्टरपंथी तत्वों का उदय और भारत-विरोधी भावनाएं क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर ख़तरा पैदा कर रही हैं।इन सब घटनाओं की पृष्ठभूमि में 2024 का छात्र-नेतृत्व वाला आंदोलन एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू हुआ यह आंदोलन

जल्द ही शेख हसीना की सरकार के खिलाफ हो गया, जिसके परिणामस्वरूप अगस्त, 2024 में हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी। इस आंदोलन में इंक़लाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी जैसे छात्र नेताओं ने प्रमुख भूमिका निभाई थी।शेख़ हसीना के जाने के बाद मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी, जिसने फरवरी, 2026 तक चुनाव कराने का वादा किया है। हालांकि, इस अवधि में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं पर हमले तथा मीडिया पर दबाव भी पड़े हैं। पिछले दिनों शरीफ उस्मान हादी की मौत हो गई। यूनुस सरकार ने इसे सुनियोजित हमला बताया और जांच का भरोसा दिलाया है। हादी की मौत के चलते ढाका में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। यह प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गया और प्रदर्शनकारियों ने प्रमुख मीडिया हाउसों को निशाना बनाया। पहले बांग्ला दैनिक 'प्रथम आलो' के कार्यालय और उसके बाद 'द डेली स्टार' की इमारत पर हमला हुआ। इन दोनों अखबारों के प्रकाशन और ऑनलाइन ऑपरेशंस प्रभावित हुए हैं। प्रदर्शनकारी इन मीडिया हाउसों को 'भारत समर्थक' या 'यूनुस सरकार समर्थक' मानते थे। कुछ रिपोर्टों में तो प्रदर्शनकारियों ने भारत को हादी की हत्या का जिम्मेदार ठहराया। इससे भारत-विरोधी नारे और बढ़ गए।इस समय बांग्लादेश में मीडिया पर हमले, प्रेस की स्वतंत्रता पर खतरा और पत्रकारों को निशाना बनाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। बेशक अंतरिम सरकार ने इन हमलों की निंदा की है, जबकि विपक्षी दल इसे सरकार की नाकामी बता रहे हैं।भारत के लिए चिंता का विषय है कि इन अख़बारों को अक्सर भारत समर्थक माना जाता है। यदि भारत-विरोधी तत्व मीडिया को निशाना बना रहे हैं, तो इससे द्विपक्षीय संबंध और भी तनावपूर्ण हो सकते हैं। भारत ने सुरक्षा कारणों से इन घटनाओं के बीच अपने वीजा आवेदन केंद्र बंद कर दिए हैं।इधर, भारत ने बांग्लादेश के राजदूत को तलब कर चिंता जताई और कट्टर तत्वों की गतिविधियों पर आपत्ति दर्ज की है। भारत का कहना है कि अंतरिम सरकार मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल रही है। हजारों बांग्लादेशी जो मेडिकल, शिक्षा या परिवार से मिलने भारत आते हैं, प्रभावित हुए हैं।हसीना सरकार के जाने के बाद जमात-ए-इस्लामी जैसे समूह सक्रिय हो गए हैं और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। भारत ने बार-बार इस पर विरोध जताया है। हादी जैसे भारत-विरोधी नेता, जो कभी 'ग्रेटर बांग्लादेश' जैसे विचारों से जुड़े थे, प्रदर्शनों में भारत को निशाना बनाकर इस भावना को प्रदर्शित करते हैं।इधर यूनुस सरकार इन तत्वों को नियंत्रित नहीं कर पा रही। चुनाव फरवरी, 2026 में हैं, लेकिन अस्थिरता से देरी हो सकती है। अस्थिरता के चलते इस समय भारतीय सीमा पर घुसपैठ, आतंकवाद या शरणार्थी संकट बढ़ सकता है।

बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति 'उथल-पुथल' जैसी है। यह एक संक्रमण काल है, जहां छात्र आंदोलन से निकले नेता, कट्टरपंथी तत्व और पुरानी पार्टियां संघर्ष कर रही हैं। इस पर भारत को सतर्क रहकर कूटनीतिक समाधान तलाशना चाहिए।

कानपुर की बंद कपड़ा मिलें फिर चालू कराने के लिए उठाएंगे आवाज

» कपड़ा कमेटी की नई कार्यकारिणी गठित, 23 सदस्य चुने गए, 28 को होगी आमसभा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। कभी 'पूर्व का मैनचेस्टर' कहलाने वाला कानपुर अपनी औद्योगिक पहचान खोता जा रहा है। शहर की लगभग सभी कपड़ा मिलें बंद होने से रोजगार पर असर पड़ा है और कपड़ा उद्योग लगभग ठप पड़ गया है। अब कानपुर कपड़ा कमेटी ने इन बंद मिलों को दोबारा शुरू कराने के लिए सरकार के सामने मांग उठाने की घोषणा की है, ताकि शहर की पुरानी चमक और रोजगार फिर लौट सके।

यह निर्णय कमेटी के कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव के बाद लिया गया। चुनाव में 851 वोट पाने वाले रुमित सिंह सांगरी ने बताया कि आने वाले दो वर्षों के लिए नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है।

23 निर्वाचित सदस्यों में से आमसभा के बाद पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा, जिसके बाद प्राथमिकता रूप में कम से कम दो कपड़ा मिलों को दुबारा शुरू कराने की पहल तेज की जाएगी।कानपुर कपड़ा कमेटी के चुनाव में कुल 1127 मतदाताओं ने मतदान किया। शुक्रवार को हुई मतगणना के बाद 23 सदस्यों का चयन किया गया। सबसे अधिक 901 वोट अमित दोसर को मिले। उनके बाद विश्वनाथ गुप्ता को 865 और रुमित सिंह सांगरी को 851 वोट मिले। अन्य सदस्यों को भी उल्लेखनीय मत प्राप्त हुए।रुमित सांगरी ने बताया कि मांग डीएम के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाएगी। जरूरत पड़ी तो प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलेगा, ताकि युवाओं को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े और शहर की औद्योगिक पहचान फिर बहाल हो सके।समिति की आमसभा 28 दिसंबर को प्रस्तावित है, जिसके बाद पदाधिकारियों का औपचारिक चयन किया जाएगा।

दहेज हत्या के मामले में तीन महीने से फरार आरोपी ससुर गिरफ्तार

» मायके वालों का आरोप, 3 लाख रुपये और मोटरसाइकिल के लिए विवाहिता को मार डाला

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। दहेज के लिए बहू की हत्या करने के मामले में वांछित चल रहे आरोपी ससुर को मंगलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी तीन महीने से फरार चल रहा था। मामला थाना कोतवाली इटावा निवासी इरफान की पुत्री नेहा से जुड़ा है। इरफान ने मंगलपुर थाने में शिकायत दर्ज करा कर आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री नेहा की शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दिए गए दहेज से खुश नहीं थे। आरोपी लगातार तीन लाख रुपये नकद और एक मोटरसाइकिल की अतिरिक्त मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर 30 सितंबर 2025 को आरोपियों ने नेहा की हत्या कर दी। इस संबंध में पुलिस ने बीएनएस की सुसंगत धाराओं और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। हत्या की वारदात के बाद से ही आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस लगातार उनकी तलाश में दबिश दे रही थी। शुक्रवार को मंगलपुर पुलिस को सूचना मिली कि दहेज हत्या का मुख्य आरोपी अफशार उर्फ मुखिया पुत्र छुट्टन कस्बा मंगलपुर के पास कब्रिस्तान के पास मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी अफशार उर्फ मुखिया को पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की संलिप्तता की भी जांच कर रही है।

एसडीएम के आदेश पर कार्रवाई शुरू, सरकारी नाले से कब्जा हटेगा

एसडीएम बिल्हौर ने दिए जांच के आदेश, कानूनगो ने सोमवार को नाला फिर खुदवाने का भरोसा दिया

» प्रमुख संवाददाता/स्वराज इंडिया

कानपुर। चौबेपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत राय गोपालपुर में प्लाटिंग के नाम पर सरकारी नाले पर कब्जे का मामला अब प्रशासनिक स्तर पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आरोपित पंकज दुबे पर दबंगई और गुंडागर्दी के दम पर नाले को पाटकर प्लाटिंग करने के गंभीर आरोप हैं। लगातार शिकायतों और मीडिया के खुलासों के बाद अब प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है।

ग्रामीणों का आरोप है कि पंकज दुबे ने सरकारी नाले की जमीन को अपनी प्लाटिंग में शामिल कर दिया, जिससे भविष्य में जलनिकासी की बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। वहीं, लेखपाल की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। सूत्रों का कहना है कि लेखपाल के संरक्षण के बिना नाले पर कब्जा संभव नहीं था।

मामले की गंभीरता देखते हुए एसडीएम बिल्हौर ने पूरे प्रकरण की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। कानूनगो मुकेश दुबे ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि सोमवार को नाले की खुदाई कर उसे दोबारा बहाल कराया जाएगा। साथ ही आरोपित भू-माफिया और सहयोगी अधिकारियों पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जाएगी।उधर, आरैपी ने नाले की जमीन पर कब्जे को कायम रखते हुए बाउंड्री तैयार कराने का काम शुरू करा दिया है। बताया जा रहा है कि पंकज दुबे पर सरकारी भूमि कब्जाने के मामले में आपराधिक मुकदमा दर्ज होने के भी प्रबल संकेत हैं।स्वराज इंडिया ने शुरुआत से इस मामले को बेबाकी से उठाया है और ग्रामीणों की आवाज प्रशासन तक पहुंचाई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सख्त कार्रवाई हुई तो भविष्य में सरकारी संपत्तियों पर कब्जे की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगेगा।

आरोपी पंकज दुबे

‘सूट-बूट’ वाले डिजिटल डकैत

जलालाबाद के खंडहर में चल रहा था फर्जी शेयर बाजार का कॉल सेंटर, छह गिरफ्तार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

शाहजहांपुर। जलालाबाद की तंग गलियों में एक पुराने खंडहर को लोग वीरान समझते रहे, लेकिन उसी खामोशी के भीतर देशभर के लोगों की गाढ़ी कमाई पर सुनियोजित तरीके से डिजिटल डाका डाला जा रहा था। शाहजहांपुर पुलिस ने शुक्रवार को एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए फर्जी शेयर बाजार कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में छह आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और लग्जरी वाहन बरामद किए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक नगर देवेंद्र कुमार के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। जलालाबाद के रुस्तमपुर इलाके में मंडी गेट के पास स्थित जिस इमारत को लोग खंडहर समझते थे, वहां ‘एसएलजी डिजी प्राइवेट लिमिटेड’ के नाम से ठगी का पूरा कॉर्पोरेट दफ्तर संचालित हो रहा था। अंदर का नजारा किसी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी से कम नहीं था।

एमबीए-एमकॉम डिग्रीधारी बना रहे थे ठगी का जाल

इस गिरोह का सरगना 31 वर्षीय टिंकल गुप्ता है, जो एमबीए पास है। उसके साथ प्रांजल सक्सेना, निहाल सक्सेना, दीपांशु, सिद्धांत मिश्रा और रोहित राठौर शामिल थे। सभी आरोपी पढ़े-लिखे हैं और जलालाबाद के ही निवासी हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी फर्जी निवेश एप और कंपनियों के नाम पर लोगों को शेयर बाजार में मोटे मुनाफे का सपना दिखाकर ठगते थे।

सस्ते में खरीदा जाता था लोगों का डेटा

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ‘सतहत्तर डाटा डॉट नेट’ जैसी वेबसाइटों से मात्र पांच हजार रुपये में एक हजार लोगों का मोबाइल डेटा खरीदते थे। इसके बाद कॉल कर निवेश के नाम पर भरोसा दिलाया जाता और रकम फर्जी खातों में ट्रांसफर करवा ली जाती थी। कुछ ही समय में पैसा अलगङ्गअलग खातों के जरिए गायब कर दिया जाता।

प्रतिबिंब पोर्टल से खुला राज

एक संदिग्ध मोबाइल नंबर की लोकेशन लगातार उसी इलाके में मिलने पर पुलिस को शक हुआ। प्रतिबिंब पोर्टल की मदद से लोकेशन ट्रेस कर साइबर टीम ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान बरामद सामान देखकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए।

बरामदगी में शामिल हैं

- 69 लैपटॉप
- 26 नए सिम कार्ड
- 10 मोबाइल फोन
- 4 वाई-फाई सेटअप
- चेकबुक
- एक महिंद्रा थार वाहन
- चार मोटरसाइकिल

गंभीर धाराओं में मुकदमा

पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 338, 336(3) सहित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इस सफल खुलासे पर पुलिस अधीक्षक ने टीम को 25 हजार रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है।

समाज के लिए चेतावनी

यह मामला एक बार फिर सवाल खड़ा करता है कि पढ़ाङ्गलिखा युवा, जो देश की अर्थव्यवस्था और समाज को मजबूत कर सकता है, आखिर शॉर्टकट के लालच में अपराध की राह क्यों चुन रहा है। फिलहाल, जलालाबाद का यह फर्जी कॉल सेंटर बंद हो चुका है और इसके ‘सीईओ’ समेत पूरा प्रबंधन जेल की सलाखों के पीछे है।

जिला कारागार: जिला जज, डीएम व पुलिस अधीक्षक ने किया संयुक्त निरीक्षण

बंदियों को मानवीय और मूलभूत सुविधाएं मिलना आवश्यक

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। शुक्रवार को जिला कारागार में व्यवस्थाओं और बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का व्यापक निरीक्षण किया गया। यह संयुक्त निरीक्षण जनपद न्यायाधीश रविन्द्र सिंह, जिलाधिकारी कपिल सिंह तथा पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय द्वारा किया गया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जेल परिसर का भ्रमण किया और बंदियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं जानीं। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन किया गया तथा भोजन व्यवस्था और उसकी गुणवत्ता की भी जांच की गई। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने जेल में चिकित्सक की नियमित उपलब्धता, दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश जेल अधीक्षक को दिए। उन्होंने कहा कि बंदियों को मानवीय और मूलभूत सुविधाएं मिलना आवश्यक है तथा इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। निरीक्षण के समय जेल अधीक्षक धीरज सिन्हा, कारपाल विजय कुमार पाण्डेय, राजेश कुमार, विजय लक्ष्मी सिंह, आरती शर्मा एवं चिकित्साधिकारी डॉ. कुलदीप सिंह सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

बम्बी में पानी काटने से जलमग्न हुई फसलें, किसानों के बहे आंसू

किसानों की मांग, अगर फसल खराब हुई तो जिला प्रशासन दे मुआवजा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। बिना जानकारी के अचानक बम्बी में पानी छोड़ दिया गया। जिसके चलते किसानों की पकी और नई फसलें जलमग्न हो गईं। किसानों का इस पानी से भारी नुकसान हुआ किसानों ने अधिकारियों से लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की मांग की और मुआवजे की बात भी कही।

रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के अंतर्गत मल्हपुर बम्बी में अचानक पानी छोड़ दिए जाने से किसानों की कई बीघा गेहूं, लाही और आलू की फसलें जलमग्न होकर बर्बाद हो रहीं हैं। उक्त घटना से किसानों में हाहाकर मच गया है। रसूलाबाद बिल्हौर मार्ग के किनारे स्थित मल्हपुर बंबी में सिचाई विभाग के द्वारा पानी छोड़े जाने से पटरी में कटान हो गया है। जिससे गेहूं, लाही और आलू की अनेकों बीघे फसलें जलमग्न हो गईं। मौसम की मार से किसान पहले ही पीड़ित थे। अब उनकी परेशानी और बढ़ गई है। किसान दिनेंद्र कुमार ने बताया कि उनके गेहूं की सिंचाई हो चुकी थी। लेकिन अचानक पानी आने से कई बीघा फसल बर्बाद हो गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि धान के सीजन में समय पर पानी नहीं मिलता। जिससे फसलें सूख जाती है। किसान प्रदीप मिश्रा के अनुसार, उनकी दो बीघा गेहूं और 10 बिस्वा आलू की

फसल पानी भर जाने से बर्बाद हो गई है। किसानों का आरोप है कि माइनर में आगे सिंचाई विभाग और राजस्व की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके कारण सफाई कार्य अधूरा रह गया। इसी वजह से पानी मल्हपुर बंबी तक सीमित रहा और आगे नहीं बढ़ पाया। जिससे यह स्थिति आई है।

क्या बोले विभाग के अफसर

सिंचाई विभाग की जेई मानसी वर्मा ने बताया कि रात में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पानी खोल दिया गया था। तेज बहाव के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पानी बंद कराया गया है।

3 मीटर सड़क चौड़ीकरण से मिलेगी राहत, अब कानपुर जाना होगा आसान

» जल्द शुरू हो जाएगा काम, कहिंजरी से रसूलाबाद तक अभी करना होगा इंतजार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। स्टेट हाईवे में 3 मीटर सडक़ की चौड़ाई बढ़ जाने से आवागमन में आसानी होगी इसके साथ ही कानपुर की दूरी कम समय में तय होगी। स्टेट हाइवे 68 शिवली से रसूलाबाद रोड दो लेन से उच्चीकृत कर तीन लेन बनाया जाएगा। फिलहाल अन्य चौड़ीकरण का कार्य बिकरु गांव के मोड तक चल रहा है उधर कार्य पूरा होने के बाद कहिंजरी बन्नापुर तक सडक़ चौड़ीकरण का कार्य तेजी से शुरू हो जाएगा। जिसके बाद रोड दस मीटर चौड़ा हो जाएगा। जिसको बनाने में करीब 50 करोड़ का खर्चा आएगा।

इस निर्माण के लिए शासन ने बजट स्वीकृत कर दिया है। सडक़ चौड़ीकरण के लिए शासन को प्रस्ताव को भेजा गया था। जिसको हरी झंडी मिल गई है।अब दोनों तरफ डेढ़ डेढ़ मीटर रोड चौड़ा किया जाएगा। रोड चौड़ा होने पर कई जिलों के लोगों को आवागमन में सहूलियत होने लगेगी। स्टेट हाइवे 68 चौबेपुर से रसूलाबाद करीब 46 किलोमीटर लंबा है।14 किलोमीटर का हिस्सा कानपुर नगर में प?ता है। वहां चौबेपुर से लेकर बिकरू मो? तक सडक़ चौड़ीकरण का काम पहले से ही हो रहा है। शिवली से रसूलाबाद तक करीब 32 किलोमीटर हिस्सा कानपुर देहात में पड़ता है। वर्तमान में सडक़ सात मीटर चौड़ी है। चौड़ाई बढऩे पर सडक़ 10 मीटर चौड़ी हो जाएगी। पांडव नदी शिवली से बन्नापुर बंबा तक पंद्रह किलोमीटर सडक़ तीन मीटर और चौड़ी होगी। उक्त मार्ग चौड़ीकरण से वाहन फर्राटा भरेंगे और कम समय में कानपुर तक की दूरी तय करेंगे। इस सडक़ से कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर, लखनऊ, दिल्ली, औरेया, बिधूना, माती, इटावा सहित अन्य जगहों के लिए वाहन चलते हैं। टोल बचाव के लिए अधिकतर वाहन चालक औरैया और इटावा जाने के लिए इसी मार्ग का चयन करते हैं।

क्या बोले जिम्मेदार

चौबेपुर बेला रोड स्टेट हाइवे 68 के 15 किलोमीटर सडक़ को सात मीटर से दस मीटर चौड़ा करने का प्रस्ताव भेजा गया था। 50 करोड़ रुपए की लागत से सडक़ चौड़ा करने का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है।

महेश कुमार
जेई लोक निर्माण विभाग

पान, परचून की दुकान पर बिक रही अवैध शराब पकड़ी गई

» आबकारी विभाग ने छापा मार कर दो लोगों को दबोचा, शराब बरामद

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जनपद में अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शुक्रवार को रनियां थाना क्षेत्र के उमरन और रनियां पड़ाव में छापेमारी कर टीम ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुल 265 क्वार्टर देसी शराब बरामद की गई है।

आबकारी निरीक्षक रामवीर यादव के नेतृत्व में टीम ने पहली कार्रवाई उमरन गांव में की। यहाँ एक परचून की दुकान पर अवैध रूप से शराब बेचे जाने की सूचना मिली थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने दुकान संचालक विक्रम सिंह पुत्र स्वर्गीय उमेश सिंह को धर दबोचा। तलाशी लेने पर दुकान से 40 क्वार्टर देसी शराब बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह दुकान की आड़ में शराब की अवैध बिक्री कर रहा था। दूसरी बड़ी कार्यवाही रनियां पड़ाव के पास की गई। यहाँ एक पान मसाले की दुकान पर छापेमारी के दौरान सुरेंद्र सिंह, निवासी ग्राम करबक को गिरफ्तार किया गया। सुरेंद्र के पास से 225 क्वार्टर देसी शराब बरामद हुई। आरोपी रनिया पड़ाव जैसे व्यस्त इलाके में छोटी सी दुकान की आड़ में इस अवैध धंधे को अंजाम दे रहा था। आबकारी निरीक्षक रामवीर यादव ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में किसी भी दुकान या ढाबे पर अवैध शराब की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इस तरह के औचक निरीक्षण भविष्य में भी जारी रहेंगे।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादकः अनूप कुमार RNI No.: UPHIN/2023/86769 | Email: swarajindia2023@gmail.com | Mob: 7800009853, | Website: www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

एसपी के नेतृत्व में चला 'नाइट डॉमिनेशन' अभियान, संदिग्ध लोगों की चेकिंग

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। कानपुर देहात। आम जनमानस को सुरक्षित माहौल देने के लिए पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पाण्डेय के निर्देशन में बीती रात व्यापक स्तर पर 'नाइट डॉमिनेशन' अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ने स्वयं भारी पुलिस बल के साथ थाना रनियां और गजनेर क्षेत्रों में सडक़ों पर उतरकर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन चेकिंग की।

अपराधियों की कुंडली खंगालने के साथ कोहरे से सुरक्षा के लिए लगाए गए रिफ्लेक्टर

अभियान के दौरान पुलिस ने रात 10:30 बजे के बाद सार्वजनिक स्थानों पर बेवजह घूमने वाले लोगों से पूछताछ की और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी। विशेष रूप से पिछले 6 महीनों के भीतर जेल से छूटे आदतन अपराधियों (चोरी, लूट व डकैती के आरोपियों) के ठिकानों पर दबिश देकर उनका भौतिक सत्यापन किया गया, ताकि वे पुन: किसी अपराध में संलिप्त न हो सकें।

कोहरे के चलते यातायात सुरक्षा पर जोर

बढ़ती ठंड और घने कोहरे के कारण होने वाली सडक़ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात पुलिस ने विशेष सक्रियता दिखाई। अभियान के दौरान वाहनों पर 'रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप' लगाए गए, जिससे कम दृश्यता में भी वाहन दूर से नजर आ सकें। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह टेप कोहरे के दौरान सडक़ हादसों को कम करने में मील का पत्थर साबित होंगे। एसपी श्रद्धा नरेंद्र पाण्डेय ने लोगों से अपील की कि यदि उन्हें अपने आसपास कोई भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति दिखाई दे, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इस अभियान में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रणनीति बनाकर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की।

सर्द रात में दो घरों के ताले टूटे लाखों के जेवर और नकदी पार

» चोरों ने परिजनों को कमरों में कैद कर वारदात को दिया अंजाम

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र अंतर्गत नंगापुर गांव में बीती रात बेखौफ चोरों ने दो मकानों को निशाना बनाया। चोरों ने बड़ी चालाकी से घर में घुसकर करीब 9 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और 70 हजार रुपये की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। आहट होने पर जब परिजनों ने शोर मचाया, तो चोर छत के रास्ते भाग निकले। इस बड़ी चोरी से इलाके में दहशत है।

नंगापुर निवासी परशुराम के मुताबिक, पूरा परिवार घर के अलग-अलग कमरों और बरामदे में सो रहा था। आधी रात को चोर मकान के पिछले हिस्से में बने शौचालय के सहारे छत पर चढ़ गए। वहां से चोर बिना दरवाजे वाले जीने के रास्ते सीधे घर के अंदर दाखिल हुए। चोरों ने कमरों का ताला तोडक़र अलमारी और बक्सों को खंगाला। यहां से चोरों ने 50 हजार रुपये नकद और करीब 8 लाख रुपये के कीमती आभूषण, जिसमें हार, जंजीर, अंगूठियां और अन्य जेवर शामिल थे,

चोरी कर लिए। चोरी के दौरान जब बहू रोशनी की नींद खुली, तो उसने शोर मचाना शुरू किया। चोरों ने पकड़े जाने के डर से कमरों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए थे, जिससे परिजन बाहर नहीं निकल सके। शोर सुनकर परशुराम के बेटे सूर्य प्रताप ने बगल में रहने वाले चचेरे भाई को फोन किया, जिसने छत से आकर नीचे का दरवाजा खोला। तब तक चोर कीमती सामान लेकर भाग चुके थे।

पड़ोसी के घर में भी की हाथ साफ

परशुराम के घर के ठीक बगल में रहने वाले देवेंद्र सिंह के मकान को भी चोरों ने इसी अंदाज में निशाना बनाया। वहां भी चोरों ने छत के रास्ते कमरे में घुसकर अलमारी और बक्सों के ताले तोड़े। देवेंद्र के घर से चोरों ने 20 हजार रुपये नकद और करीब 50 हजार रुपये के आभूषण चोरी किए। पड़ोस में शोर सुनकर जब देवेंद्र के बेटे विनय ने बाहर निकलना चाहा, तो उसका कमरा भी बाहर से बंद मिला। पुलिस क्षेत्राधिकारी संजय सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौका मुआयना किया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

चोरों ने अलमारी, बक्से तोड़ दिए

(योगी-अखिलेश आमने-सामने)

नकली कोडीन कफ सिरप तस्करी पर सियासी संग्राम !

» मुख्यमंत्री योगी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में सक्रिय रहे अधिकांश माफियाओं के तार किसी न किसी रूप में सपा से जुड़े रहे हैं

» अखिलेश यादव का कहना है कि योगी सरकार अपनी प्रशासनिक नाकामियों से जुड़े सवालों से ध्यान हटाने के लिए विपक्ष को निशाना बनाती है

»प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर तीखे आरोप-प्रत्यारोप के दौर में पहुंच गई है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले कोडीन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच खुला सियासी टकराव देखने को मिल रहा है। मामला अब केवल नशीली दवाओं की तस्करी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि राजनीतिक संरक्षण, माफिया नेटवर्क और हजारों करोड़ रुपये के अवैध कारोबार के आरोपों के साथ बड़े राजनीतिक संघर्ष का रूप ले चुका है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत में समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में सक्रिय रहे अधिकांश माफियाओं के तार किसी न किसी रूप में सपा से जुड़े रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कोडीन कफ सिरप तस्करी के मामले में पकड़े गए कुछ अभियुक्तों के संबंध भी सपा से सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष उसी के बाद सामने आएगा, लेकिन प्रारंभिक तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि जब अभियुक्तों के साथ राजनीतिक नेताओं की तस्वीरें सामने आती हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है।

योगी आदित्यनाथ ने शायराना अंदाज़ में सपा नेतृत्व पर तंज कसते हुए कहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। उनके इस बयान को सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकार किसी भी दोषी को बख्शने के मूड में नहीं है, चाहे उसका संबंध किसी भी दल या प्रभावशाली व्यक्ति से क्यों न हो।

मुख्यमंत्री के बयान के कुछ ही समय बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से पलटवार किया। बिना नाम लिए शायरी के अंदाज़ में उन्होंने कहा कि जब खुद फंस जाओ तो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना आसान होता है। सपा नेताओं का कहना है कि योगी सरकार अपनी प्रशासनिक नाकामियों और कानून-व्यवस्था से जुड़े सवालों से ध्यान हटाने के लिए विपक्ष को निशाना बना रही है।

यह मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि कोडीन फॉस्फेट सीधे तौर पर एनडीपीएस अधिनियम से जुड़ी नियंत्रित औषधि है।

जांच एजेंसियों के मुताबिक वाराणसी, जौनपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और सोनभद्र जैसे जिलों में एक संगठित नेटवर्क सक्रिय था, जो फर्जी लाइसेंस, शेल कंपनियों और जाली दस्तावेजों के सहारे कफ सिरप की अवैध सप्लाई कर रहा था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 37 लाख से अधिक बोतलों की अवैध बिक्री सामने आ चुकी है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 57 करोड़ रुपये बताई जा रही है, जबकि पूरे सिंडिकेट का कारोबार करीब 2,000 करोड़ रुपये तक आंका जा रहा है।

जांच में यह भी सामने आया है कि यह सिरप उत्तर प्रदेश से बिहार, पश्चिम बंगाल और सीमा पार तक भेजा जा रहा था। शराबबंदी वाले राज्यों में इसकी मांग अधिक थी, जहां इसे नशे के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। इस रैकेट का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल बताया जा रहा है, जो वाराणसी का मेडिकल सप्लायर था और जिसने कथित तौर पर कोरोना काल के दौरान इस अवैध कारोबार को तेजी से फैलाया। फिलहाल वह फरार है और उसके दुबई में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है।

सरकार ने मामले की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय विशेष जांच टीम गठित की है, जिसमें यूपी पुलिस, एसटीएफ और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू कर दी है। अब तक 12 से अधिक दवा कारोबारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों की कुर्की की तैयारी भी चल रही है।

इस पूरे विवाद के बीच विधानसभा का शीतकालीन सत्र राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। सत्र 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलेगा। माना जा रहा है कि कोडीन कफ सिरप तस्करी का मुद्दा सदन के भीतर और बाहर तीखी बहस का केंद्र बनेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों की राजनीति पर भी गहरा असर डाल सकता है। एक ओर योगी सरकार इसे नशामुक्त प्रदेश और माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के रूप में पेश कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दे रही है। फिलहाल पूरे प्रदेश की निगाहें जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई और उसके निष्कर्षों पर टिकी हैं।

एसपी ने सड़कों पर उतरकर किया पैदल गस्त, दिलाया सुरक्षा का भरोसा

औरैया। जनपद में शांति,सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से औरैया पुलिस ने शुक्रवार को विशेष पैदल गश्त अभियान चलाया।इस दौरान एसपी अभिषेक भारती स्वयं पुलिस बल के साथ देर रात्रि कोतवाली दिबियापुर क्षेत्र पहुंचकर पुलिस सहायता केन्द्र का औचक निरीक्षण कर रात्रि गश्त में लगे सभी अधिकारी और कर्मचारियों को चेक किया गया तथा ही उन्होंने मुख्य मार्गों,बाजारों और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर पैदल गश्त पर निकले।एसपी ने क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए आमजन से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनीं और सुरक्षा को लेकर आश्वासन दिया।दुकानदारों व राहगीरों को सतर्क रहने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों का स्वयं गश्त में शामिल होना न केवल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करता है,बल्कि जनता के बीच भरोसा भी बढ़ाता है।औरैया पुलिस ने बताया कि इस प्रकार का पैदल गश्त अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा,ताकि जनपद में शांति और कानून-व्यवस्था अक्षुण्ण रहे।

चाकू दिखा कर आंगनबाड़ी कार्यकत्री की अस्मत लूटने का आरोप

थाने की चौखट पर न्याय अटका, दुष्कर्म के बाद भी खामोश पुलिस

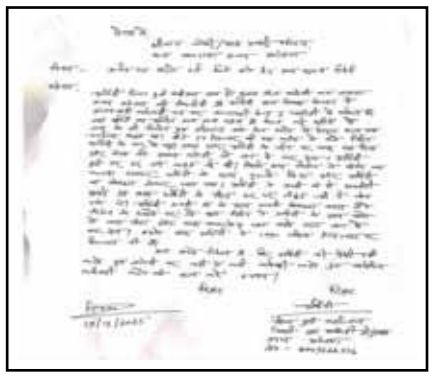

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या।रामनगरी के खंडासा थाना क्षेत्र से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां गांव की ही एक आंगनबाड़ी कार्यकत्री ने युवक पर घर में घुसकर चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। पीड़िता न्याय की गुहार लेकर थाने की चौखट तक पहुंची, लेकिन हैरानी की बात यह है कि गंभीर आरोपों के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।

पीड़िता के अनुसार, आरोपी युवक पहले से ही उसे निशाना बनाए हुए था। आंगनबाड़ी केंद्र जाते समय रास्ते में छेड़छाड़ उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। आरोप है कि 17 सितंबर की रात, पिता की गैरमौजूदगी में आरोपी घर में घुस आया। गले पर चाकू रखकर जान से मारने की धमकी दी और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जाते-जाते आरोपी युवती का मोबाइल फोन भी उठा ले गया। घटना के बाद दहशत और सदमे में डूबी युवती ने मां को पूरी आपबीती बताई। मां के साथ जब वह आरोपी के घर मोबाइल मांगने पहुंची तो कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की गई।

पीड़िता ने पूरे घटनाक्रम की लिखित तहरीर पुलिस को सौंपी है। प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र कुमार सोनकर का कहना है कि तहरीर प्राप्त हुई है, आरोपी को बुलाकर जांच की जा रही है और जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जब आरोप इतने गंभीर हैं तो कार्रवाई जांच के बाद क्यों, तत्काल क्यों नहीं? इस घटना ने क्षेत्र में आक्रोश पैदा कर दिया है। ग्रामीणों में चर्चा है कि अगर आंगनबाड़ी कार्यकत्री जैसी महिला भी सुरक्षित नहीं है तो आम बेटियों का क्या होगा?

अयोध्या में ठंड से कांपती आवाम, नगर निगम की फाइलों में जलते अलाव!

» सत्ता पक्ष के पार्षद प्रतिनिधि नगर निगम पर संगीन आरोप लगा रहे

» नगर निगम कर रहा दावा, 60 वार्ड में जलाए जा रहे 45 अलाव

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या।जिस अयोध्या को पूरी दुनिया आस्था की राजधानी मानती है, उसी रामनगरी में आज सर्द रातों में गरीब, बुजुर्ग और राहगीर अलाव की तलाश में ठिठुरते फिर रहे हैं और नगर निगम है कि प्रेस विज्ञप्तियों में अलाव जलाकर वाहवाही लूट रहा है। हकीकत इतनी तल्ख है कि सत्ता पक्ष के पार्षद प्रतिनिधि खुद नगर निगम पर संगीन आरोप लगा रहे हैं।

मणिराम दास छावनी वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि रिशु पांडे का आरोप सीधे सिस्टम के मुंह पर तमाचा है। उनका कहना है कि वार्ड में 16 अलाव पॉइंट चिन्हित हैं, लेकिन ज़मीन पर एक भी अलाव नहीं जल रहा। यही नहीं महापौर आवास और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी का निवास स्थान भी इसी इलाके में आता है। सवाल उठता है अगर यहां अलाव नहीं, तो शहर के बाकी वार्डों की हालत क्या होगी? हनुमान कुंड वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि अभय श्रीवास्तव ने आरोपों को और धार दी। उनका कहना है अलाव जलाने की पूरी व्यवस्था कागज़ों में है। हमारे वार्ड के 16 में से एक भी पॉइंट पर अलाव नहीं जल रहा। यानि नगर निगम ने लकड़ी नहीं, सिर्फ कागज़ जलाए हैं। टेंडर ही नहीं हुआ, फिर अलाव कैसे?

स्वराज इंडिया को नगर निगम के एक जिम्मेदार अधिकारी ने जो बताया, उसने पूरे दावे की पोल खोल दी। अधिकारी के मुताबिक अभी तक नगर निगम द्वारा अलाव जलाने का टेंडर ही नहीं हुआ है। नगर आयुक्त के विशेषाधिकार से कुछ चुनिंदा प्वाइंटों पर लकड़ी जलाने की व्यवस्था कराई जा रही है। तो फिर सवाल साफ है जब टेंडर नहीं, तो 45 अलाव किस आधार पर जलने का दावा किया जा रहा है? हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सत्ता पक्ष के पार्षद भी नगर निगम पर सवालों की बौछार कर रहे हैं। महापौर से जब इस मुद्दे पर वार्ता की गई तो जवाब मिला हम बाहर हैं, कल आकर व्यवस्था देखेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है की क्या ठंड कल तक रुक जाएगी? क्या अलाव देखने से जल जाएंगे?

60 वार्ड, 45 अलाव जल रहे!

नगर निगम की प्रेस विज्ञप्ति दावा करती है कि शहर के 60 वार्डों में 45 पॉइंट पर अलाव जल रहे हैं। जबकि जमीनी सच्चाई ये है कि वार्ड दर वार्ड अलाव नदारद हैं। यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि गरीबों की ठंड से हो रही पीड़ा पर खुला मज़ाक है। नगर निगम क्षेत्र की जनता सवाल पूछ रही है अलाव जल रहे हैं या सिर्फ रिपोर्टें गरम की जा रही हैं? रामनगरी में ठंड से कांपते लोग किससे उम्मीद करें फाइलों से या ज़मीन से? अगर यही हाल रहा, तो अयोध्या में सर्दी नहीं नगर निगम की बेरुखी सबसे ज्यादा जमा देगी।

श्री अवधधाम महोत्सव शुरू, 15 दिनों तक होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम

अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान बन चुका अवधधाम महोत्सव

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। श्री अवधधाम महोत्सव का भव्य शुभारंभ नाका स्थित नीलकंठ मैरिज लॉन में हुआ। महोत्सव का उद्घाटन पूर्व सांसद लल्लू सिंह द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता अभिषेक मिश्रा एवं आकाशमणि त्रिपाठी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उद्घाटन अवसर पर अतिथियों ने श्री अवधधाम महोत्सव को अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त करने वाला आयोजन बताया और इसकी सफलता के लिए आयोजन समिति को शुभकामनाएँ दीं।

इस महोत्सव के अध्यक्ष मोहित महाराज हैं। उद्घाटन समारोह में आयोजन समिति के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें किशन प्रजापति, शुभांकर वर्मा, वैभव शुक्ला, पारुल शर्मा, चंचल मोदनवाल, अनुष्का गुप्ता, मंतसारी जावान, अमन यादव, सौरव वर्मा, ओम रमानी सहित अन्य सभी सहयोगी शामिल रहे।

महोत्सव के अंतर्गत 'एक शाम शहीदों के नाम' कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा शहीद परिवारों का सम्मान किया गया।

महोत्सव 15 दिनों तक चलेगा जिसमें प्रतिदिन भजन संध्या, कवि सम्मेलन, डांसिंग, सिंगिंग, फैशन शो, भोजपुरी नाइट, अवधी नाइट, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रम, साथ ही झूले व दुकानें आकर्षण का केंद्र रहेंगी।

अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में साहित्यकार डॉ. मेघा का सम्मान

शॉल, स्मृति चिह्न व एक लाख रुपये का चेक दिया गया

अयोध्या। श्रीरामचरितमानस भवन, अयोध्या में आयोजित अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. मेघा अग्रवाल को उनके उल्लेखनीय साहित्यिक योगदान एवं समाज सेवा के लिए सम्मानित किया गया। डॉ. मेघा अग्रवाल साहित्य के क्षेत्र में देश-विदेश में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकी हैं और वर्तमान में साहित्य जगत की गौरवशाली हस्ती मानी जाती हैं। उन्हें साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, समाज के प्रति समर्पण तथा वैश्य समाज के उत्थान हेतु की गई सराहनीय सेवाओं के लिए रामदास अग्रवाल जन सेवा सम्मान से अलंकृत किया गया।

यह सम्मान अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रदान किया गया। सम्मान स्वरूप डॉ. मेघा अग्रवाल को शॉल, स्मृति चिह्न (मुमेंटो) एवं एक लाख रुपये की धनराशि का चेक प्रदान किया गया। सम्मान प्राप्त करने के पश्चात डॉ. मेघा अग्रवाल ने कहा कि यह सम्मान उन्हें साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में और अधिक समर्पण के साथ कार्य करने की प्रेरणा देगा। इस अवसर पर नवनीत कुमार सान्टू, अवधेश लड्ढा, हरि अग्रवाल भी मौजूद रहे।

पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधन में ममता बनर्जी पर बोला हमला

बंगाल में टीएमसी का जंगलराज, घुसपैठियों को बचाने की कोशिश

- कहा- बिहार ने दिया मौका, अब बंगाल की बारी।
- बंगाल सरकार सिर्फ कट और कमीशन में लगी रहती है।
- पश्चिम बंगाल की यह भूमि वंदे मातरम् के अमरगान की भूमि है: प्रधानमंत्री

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में एसआईआर के दौरान 58 लाख नाम डिलीट किए जाने के बाद बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी ने शनिवार को नादिया जिले में आने वाले राणाघाट की रैली को मोबाइल से संबोधित किया। खराब मौसम के कारण पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी भाजपा का विरोध करना चाहती है। उन्हें हमारा जमकर बार-बार, पूरी ताकत से विरोध करने दीजिए। मुझे समझ नहीं आता कि पश्चिम बंगाल के विकास में रुकावट क्यों डाली जा रही है। आप मोदी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन बंगाल के लोगों को दुखी मत कीजिए। उन्हें उनके अधिकारों से वंचित मत कीजिए। उनके सपनों को तोड़ने का पाप मत कीजिए। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में घुसपैठियों को बचाने की कोशिश हो रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह ममता बनर्जी उन घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं जो पश्चिम बंगाल पर कब्जा करने पर तुले हुए हैं। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल में एसआईआर का विरोध कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल के लोगों से हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि भाजपा को एक मौका दें। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश तेज़ी से विकास चाहता है। आपने देखा कि पिछले महीने ही बिहार ने विकास के लिए एनडीए सरकार को भारी बहुमत दिया। बिहार में बीजेपी-एनडीए की बड़ी जीत के बाद मैंने कहा था कि गंगा बिहार से बंगाल तक बहती है। इसलिए बिहार ने बंगाल में भी बीजेपी की जीत का रास्ता साफ कर दिया है।

कोहरा बन गया रैली में रोड़ा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भारी भीड़ उमड़ी थी। पीएम मोदी ने सर्वप्रथम मैं आपसे क्षमाप्रार्थी हूं कि मौसम खराब होने की वजह से मैं आपके बीच उपस्थित नहीं हो सका। कोहरे की वजह से वहां हेलिकॉप्टर उतरने की स्थिति नहीं थी, इसलिए मैं आपको टेलीफोन के माध्यम से संबोधित कर रहा हूं। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि रैली स्थल पर पहुंचते समय खराब मौसम की वजह से भाजपा परिवार के कुछ कार्यकर्ता रेल हादसा के शिकार हुए हैं। जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की दुखद मृत्यु हुई है, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दुख की इस घड़ी में हम सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं।

100 रुपये तक महंगी हो सकती है अंग्रेजी बोतल

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शराब के शौकीनों के लिए एक बुरी खबर आ रही है। अगले साल से शराब के दामों में बढ़ोत्तरी होने जा रही है। राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति लागू करने जा रही है, जिसके तहत शराब के दामों में बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। यह नई नीति 1 अप्रैल से लागू होगी। प्रस्ताव के मुताबिक, अंग्रेजी शराब की एक बोतल 100 रुपये तक महंगी हो सकती है।

सूत्रों के मुताबिक, नई नीति लागू होने के बाद शराब की कीमतों में अलग-अलग स्तर पर बढ़ोतरी हो सकती है। क्वार्टर की कीमत में 15 से 20 रुपये, हॉफ बोतल में करीब 50 रुपये और एक फुल बोतल की कीमत में 100 रुपये तक इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कीमतों में बढ़ोत्तरी का असर मुख्य रूप से बड़े और प्रीमियम ब्रांड्स पर पड़ेगा। रेगुलर और सस्ते ब्रांड्स पर अधिक बोझ न डालने की कोशिश की जाएगी ताकि उपभोक्ताओं का रुझान अवैध शराब की ओर न जाए।

इसके साथ ही लाइसेंस फीस में भी 10 फीसदी बढ़ोत्तरी की बात कही गई है। यहीं नहीं, इस बार भी शराब की दुकानों का नवीनीकरण किया जाएगा और टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी।

फिंगर चिप्स खाया... घर पहुंचते ही शुरू हुईं उल्टियां

फतेहपुर में एक ही परिवार के नौ लोग अस्पताल में भर्ती

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक परिवार के जान पर बन आई। दरअसल, यहां शुक्रवार की शाम फिंगर चिप्स खाकर एक ही परिवार के 9 लोग बीमार हो गए। घटना से पूरे परिवार में जहां चीख-पुकार मच गई, तो वहीं ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सभी को आनन-फानन में सीएचसी में भर्ती कराया गया। जहां सभी का इलाज चल रहा है।

जानकारी के अनुसार, थरियांव थाना के मलांव गांव के रहने वाले ज्ञान सिंह लोधी शुक्रवार की शाम परिवार की अमृता देवी, बड़की, ज्ञानमती, गायत्री, फूलदुलारी, सोनी, सुलोचना और मिथुन को साथ लेकर थाना क्षेत्र के ही अंबापुर गांव में रिश्तेदारी के एक निमंत्रण में गए थे। जहां से वापस घर लौट रहे थे, इसी दौरान शाम करीब 6:30 बजे उपरोक्त लोग रामपुर थरियांव गांव के पास स्थित तिराहे पर पहुंचे और सड़क किनारे ठेले में लगी फास्ट फूड की दुकान से आलू का फिंगर खरीद कर खा लिया।

इसके बाद गांव के लिए चल पड़े। बताया जा रहा है कि जैसे ही यह सभी लोग घर पहुंचे, तो एक-एक करके सभी को उल्टियां शुरू हुईं और हालत बिगड़ गई। एक साथ सभी की अचानक हालत बिगड़ती देख आस-पड़ोस के लोग आनन-फानन में सभी को थरियांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर मौजूद डॉक्टरों ने भर्ती कर सभी का इलाज शुरू किया।

चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सौरभ जायसवाल ने बताया कि फूड प्वाइजनिंग की वजह से उल्टियां शुरू हुईं। सभी की हालत बिगड़ गई थी। सभी लोगों का इलाज जारी है। फिलहाल हालत में सुधार है।

भाजपा नेता प्रीतम सिंह समेत छह पर कोर्ट के आदेश पर एफआईआर

55 दिन से लापता, फटकार के बाद पुलिस ने किया था गिरफ्तार

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह किसान और उनके बेटे समेत छह लोगों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर अब संगीन धाराओं में दर्ज किया है। भाजपा नेता पर प्राणघातक हमला करने और दलित उत्पीड़न के आरोप लगाए गए है। पुलिस की इस कार्रवाई से परिजनों और भाजपा नेता के समर्थकों में हड़कंप मच गया है।

हमीरपुर जिले के राठ कस्बे के रहने वाले प्रीतम सिंह किसान लोधी जाति के है जो कई साल पहले भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे है। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी। इनके नाम किसान पेट्रोल पंप है। धनतेरस की रात इनके पेट्रोल पंप में महोबा जिले के पनवाड़ी थाना क्षेत्र के बुड़ौरा गांव निवासी नरेश अहिरवार अपने साथी मनोज, वीरेन्द्र, अजय व रवि कुमार के साथ कार से पेट्रोल पंप गए थे।

पेट्रोल भराने के बाद पेमेंट को लेकर इन लोगों का विवाद भाजपा नेता प्रीतम सिंह किसान से हो गया। दोनों में मारपीट हो गई। भाजपा नेता ने अपने लाइसेंसी रायफल से फायरिंग कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और भाजपा नेता समेत दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर कोतवाली ले गई। दूसरे पक्ष के नरेश समेत अन्य लोगों को पुलिस ने सीएचसी राठ में प्राथमिक इलाज कराया। बाद में भाजपा नेता समेत अन्य लोगों को पुलिस ने रात भर कोतवाली में बैठाए रखा। अगले दिन पुलिस ने दोनों पक्षों को आपसी समझौता के बाद कोतवाली से छोड़ दिया था, लेकिन भाजपा नेता अचानक लापता हो गए। उनके भाई वीर सिंह अधिवक्ता ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक वाद दायर कर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे।

इधर पीड़ित नरेश अहिरवार ने विशेष न्यायाधीश (एससी एसटी एक्ट) की अदालत में भाजपा नेता प्रीतम सिंह किसान समेत छह लोगों के खिलाफ वाद दायर किया था जिस पर कोर्ट ने भाजपा नेता, उनके पुत्र समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिए थे। कोर्ट के आदेश को लेकर राठ कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

हिरासत में भाजपा नेता

भाजपा नेता प्रीतम सिंह के भाई वीर सिंह ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी। कई बार तारीखें पड़ी लेकिन भाजपा नेता का कहीं कोई पता पुलिस नहीं लगा पाई थी। बीते 8 दिसंबर को हाईकोर्ट ने एसपी डॉ. दीक्षा शर्मा को तलब किया था। हाईकोर्ट में एसपी के तलब होने के बाद पुलिस ने 55 दिन से लापता भाजपा नेता को लखनऊ के दुबग्गा से एक मकान में छापेमारी कर गिरफ्तार किया। फिर हमीरपुर कोर्ट में पेश किया था, जहां से भाजपा नेता को वृद्धा आश्रम में तीन दिन तक रखा गया था।